

उत्तराखण्ड ने 89,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखण्ड सरकार ने वधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये अपना [बजट](#) पेश किया।

- वर्ष 2022-23 में उत्तराखण्ड की आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय औसत को पार करते हुए 7.63% रही।

मुख्य बट्टि:

- [गरीबी](#) को दूर करने, [आपदा प्रबंधन](#), [बुनियादी ढाँचे के विकास](#) और हवाई कनेक्टिविटी में सुधार पर ज़ोर देने वाली कई पहलों के लिये 89,000 करोड़ रुपए का आवंटन।
- बजट में [वकिसति भारत के "चार स्तंभों"](#) के प्रति समर्पण पर ज़ोर दिया गया- गरीबों का कल्याण, युवा सशक्तीकरण, [कृषि पहल](#) और [महिला सशक्तीकरण](#)।
- प्रत्येक स्तंभ के लिये किये गए प्रावधान हैं:
 - [गरीबों के कल्याण](#) के लिये 5,658 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिसमें आवास पहल, खाद्यान्न वितरण और मुफ्त गैस रफिलि योजनाएँ शामिल हैं।
 - बजट में [युवा कल्याण](#), [तकनीकी एवं उच्च शिक्षा](#) और [राष्ट्रीय खेलों](#) के आयोजन के लिये 1,679 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
 - [अल्पसंख्यक लड़कियों की योग्यता को बढ़ावा देने](#) और [रोज़गार के अवसरों](#) को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के लिये भी प्रावधान किये गए हैं।
 - [सहकारी पहल](#), [सेब की खेती](#), [किसान पेंशन](#) और [मत्स्यन विकास](#) सहित विभिन्न [किसान-केंद्रित योजनाओं](#) के लिये 2,415 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
 - [लगि-वशिष्ट पहलों के लिये बजट में लगभग 14,538 करोड़ रुपए](#) अलग रखे गए हैं।
 - इन योजनाओं का उद्देश्य [मातृ एवं शिशु कल्याण](#) और [महिलाओं की आर्थिक भागीदारी](#) को बढ़ाना है।